राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5472/2022

साहून पुत्र स्व. जमील खान, उम्र लगभग 27 वर्ष, बी/सी मोहम्मडन निवासी निभाना गांव। ग्वालदा तहसील तिजारा पी.एस. चौपानकी भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान सरकार, लोक अभियोजक के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

याचिककर्ता (गण) की ओर से	:	श्री दिनेश कुमार
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एस.के. भाटी, लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

<u>आदेश</u>

<u>27/09/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.04.2022 के आदेश (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) को चुनौती दी है। विद्वान विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी (अत्याचार मामलों की रोकथाम), उदयपुर, (इसके बाद 'पुनरीक्षण प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित किया गया, जिससे, संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर (इसके बाद 'पुनरीक्षण प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा आदेश दिनांक 08.03.2022 पारित किया गया। 'अपीलीय प्राधिकारी' के रूप में संदर्भित), विद्वान सहायक वन संरक्षक, उदयपुर (इसके बाद 'प्राधिकृत अधिकारी' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित जब्ती के आदेश दिनांक 29.11.2021 के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को अपास्त कर दिया गया है।

2. सटीक रूप से वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं कि 29.04.2021 को, सुबह 8:15 बजे या उसके आसपास, पुलिस प्राधिकरण को सूचित किया गया कि एक ट्रक जिसका संख्या RJ-14-GG 7655 (इसके बाद 'जब्त ट्रक' के रूप में जाना जाएगा) है, खैर की लकड़ी अवैध रूप से खेरवाड़ा से उदयपुर ले जा रहा है। तदनुसार, पुलिस ने ट्रक को रोका और जब्त कर लिया, जिसे शब्बीर पुत्र बशीर खान चला रहा था। एक एफआईआर संख्या 70/2021 दिनांक 29.04.2021, जिसमें राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (इसके बाद '1953 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 41 और 42 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379 (इसके बाद) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।

3. उक्त एफ.आई.आर. की सूचना प्राप्त होने पर मु.अ.सं. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ट्रक एवं माल की जप्ती की कार्यवाही हेतु दिनांक 09/2021 पंजीकृत किया गया। विद्वान विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) सराडा, उदयपुर को पत्र क्रमांक 115 दिनांक 25.08.2021 द्वारा जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के बारे में सूचना भेजी गई थी।

4. जब्ती की कार्यवाही में, आरोपी और जब्त किए गए ट्रक के चालक ने गवाही दी कि जब वह गुजरात-राजस्थान सीमा पर एक ढाबे पर खाना खा रहा था, तो एक व्यक्ति उसके पास आया और परिवहन के लिए अपने खेत से लकड़ी को हरियाणा ले जाने का अनुरोध किया जिसके लिए रुपये 70,000/- का परिवहन शुल्क देने के लिए कहा उन्होंने बताया कि वह लकड़ी/लकड़ी की प्रकृति से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे और इसके परिवहन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

5. ड्राइवर ने अपेक्षित लाइसेंस के बिना लकड़ी ले जाने की अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन 1953 के अधिनियम के तहत अपराध स्वीकार नहीं किया। जब्त किए गए ट्रक के मालिक ने कहा कि वह इस बात से अनजान था कि खैर की लकड़ी का परिवहन अवैध था और उसे इसके बारे में तब पता चला। जब पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया।

6. हालाँकि, प्राधिकृत अधिकारी ने वाहन को जब्त करने का आदेश पारित किया, जिसमें यह नोट किया गया कि यद्यपि जब्त किए गए ट्रक का उपयोग 1953 के अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत अपराध करने के लिए किया गया था, लेकिन यह वाहन के पंजीकृत स्वामी की बिना जानकारी या मिलीभगत के किया गया था। इस तरह के निष्कर्ष के

बावजूद, जब्त की गई लकड़ी और उसे ले जाने वाले वाहन को दिनांक 29.11.2021 के आदेश के माध्यम से जब्त कर लिया गया। दिनांक 29.11.2021 के आदेश में बताए अनुसार इस तरह की जब्ती का कारण यह था कि ऐसे अपराध करने की संख्या बढ़ रही है और लकड़ी के ऐसे अवैध परिवहन/व्यापार से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

7. वाहन के पंजीकृत मालिक ने मुख्य वन संरक्षक - अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की, जिसने प्राधिकृत अधिकारी की अपील को अपास्त कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ 1953 के अधिनियम की धारा 52ख के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसने पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए अपास्त कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कानून की कोई त्रुटि नहीं बताई गई है और तथ्यात्मक प्रस्तुतियाँ की गई हैं पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष मुख्य मामले में न्यायालय द्वारा जांच की जानी है।

8. अंतः, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब्ती का आदेश अपराध के मुकदमे के निष्कर्ष या अभियुक्त की दोषसिद्धि के बिना पारित किया गया है, इसलिए इसे अपास्त किया जाए।

10. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका 1953 के अधिनियम की धारा 52ख(5) में निहित वैधानिक रोक के आलोक में विचारणीय नहीं है। इस तरह के विवाद को समर्थन देने के लिए, विद्वान लोक अभियोजक ने इसका हवाला दिया। **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2019 की **आपराधिक अपील संख्या 524 @ एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2001/2012** में दिया गया निर्णय।

11. प्रतिद्वंद्वी के अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

12. आक्षेपित आदेश की वैधता और औचित्य पर चर्चा करने से पहले 1953 के अधिनियम की योजना की रूपरेखा तैयार करना उचित होगा, जिसके लिए, उसके संबंधित भाग यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"42. धारा 41 के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना -

(1) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 41 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे छह माह तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जिसे पच्चीस हजार रुपये या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

(2) ऐसे मामले में जहां उप-धारा (1) के तहत अपराध सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले या वैध प्राधिकारी के प्रतिरोध की तैयारी के बाद किया जाता है या जहां अपराधी को पहले इसी तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, दंड दोगुना होगा उपधारा (1) में उल्लिखित है।

बल दिया गया

52. जब्ती योग्य संपत्ति की जब्ती. - (1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वन उपज के संबंध में वन अपराध किया गया है, तो ऐसी उपज, सभी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियाँ, जंजीरें या उपयोग की गई कोई अन्य वस्तु सहित ऐसे किसी भी अपराध को करने पर, किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है जो हेड कांस्टेबल से कम रैंक का न हो।

...

(3) उप-धारा (5) के अधीन, जहां प्राधिकृत अधिकारी, जब्त की गई संपत्ति के समक्ष प्रस्तुत होने पर या जब्ती के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि उसके संबंध में वन अपराध किया गया है , वह लिखित आदेश द्वारा और दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इस तरह के अपराध को करने में इस्तेमाल की गई सभी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु के साथ जब्त की गई वन-उपज को जब्त कर सकता है। जब्ती के आदेश की एक प्रति बिना किसी अनुचित देरी के उस क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक को भेज दी जाएगी जिसमें वन उपज जब्त की गई है।

(4) किसी भी संपत्ति को जब्त करने का कोई भी आदेश उप-धारा (3)

के तहत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिकृत अधिकारी न हो

(क) संपत्ति की जब्ती के लिए कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्धारित प्रपत्र में उस अपराध की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को सूचना भेजता है जिसके कारण जब्ती की गई है;

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे संपत्ति जब्त की गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को, जो प्राधिकृत अधिकारी के सामने ऐसी संपत्ति में कुछ रुचि रखता हो, लिखित में नोटिस जारी करता है;

(ग) खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों को एक अवसर प्रदान करता है

(b) प्रस्तावित ज़ब्ती के विरुद्ध नोटिस में निर्दिष्ट उचित समय के भीतर अभ्यावेदन देना; और

(घ) जब्ती करने वाले अधिकारी और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें खंड(ख) के तहत नोटिस जारी किया गया है, ऐसे उद्देश्य के लिए तय की जाने वाली तारीख पर सुनवाई देता है।

(5) किसी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियाँ, जंजीरें या कोई अन्य वस्तु (जब्त की गई लकड़ी या वन उपज के अलावा) की उपधारा (3) के तहत जब्ती का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के खंड(ख) में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध होता है कि ऐसी किसी भी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सियाँ, जंजीरें या कोई अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था। या जैसा भी मामला हो, अपने नौकर या एजेंट की जानकारी या मिलीभगत के बिना और वन अपराध के लिए उपरोक्त वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ सभी उचित और आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं।

बल दिया गया

52क. ज़ब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील - (1) ज़ब्ती के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश के तीस दिनों के भीतर, या यदि ऐसे आदेश का तथ्य उसे सूचित नहीं किया गया है, तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, लिखित रूप में ऐसी फीस के साथ अपील कर सकता है और ऐसे निर्धारित प्रारूप में देय होगा और जब्ती के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ उस वन क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक (इसके बाद इस अध्याय में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) को भेजा जाएगा जिसमें वन उपज होती है, जब्त कर लिया गया है...

बल दिया गया

52ख. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। - (1) अपील का कोई भी पक्ष, अंतिम आदेश या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित परिणामी प्रकृति के आदेश से व्यथित, जिस आदेश पर आपत्ति की जानी है उसके तीस दिनों के भीतर, सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है। सत्र प्रभाग जिसमें अपीलीय प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है।

...

(4) इस धारा के तहत एक पुनरीक्षण पर विचार करने, सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए, सत्र न्यायालय, जहां तक संभव हो, समान शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसाकि वह एक पुनरीक्षण पर विचार करने, सुनवाई करने और निर्णय लेने के दौरान करता है और अपनाता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2)।

(5) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इस धारा के तहत पारित सत्र न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और किसी अदालत

के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

बल दिया गया

52ग. कुछ परिस्थितियों में न्यायालय आदि के क्षेत्राधिकार पर रोक - (1) धारा 52 की उप-धारा (4) के तहत उस अपराध की सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति की जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, जिसके कारण संपत्ति की जब्ती की गई है, जो जब्ती का विषय है , बनाया गया है, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और धारा 52, 52-ए और 52-बी में निर्दिष्ट सत्र न्यायालय के अलावा) के पास इस संबंध में आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। संपत्ति के कब्जे, वितरण, निपटान या वितरण के संबंध में, जिसके संबंध में जब्ती की कार्यवाही धारा 52 के तहत शुरू की जाती है, इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी विपरीत बात के बावजूद।

...

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात धारा 61 के तहत बचाई गई बिजली को प्रभावित नहीं करेगी।

बल दिया गया

55. वन उपज, औजार आदि जब जब्ती के योग्य हों - (1) सभी लकड़ी या वन उपज जो राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है और जिसके संबंध में वन अपराध किया गया है, और सभी मशीनरी, हथियार, लिखत, नाव, मवेशी, वाहन, रस्सी, चेन या कोई अन्य लेख किसी भी वन अपराध को करने में उपयोग किया गया, धारा 52, 52-ए, 52-बी और 52-सी के प्रावधानों के अधीन, ऐसे वन अपराध के लिए अपराधी को दोषी ठहराए जाने पर जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) ऐसी ज़ब्ती ऐसे अपराध के लिए निर्धारित किसी अन्य सज़ा के

अतिरिक्त हो सकती है।

"बल दिया गया

13. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि जहां 1953 के अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया पाया जाता है, तो दोषसिद्धि के निर्णय पर सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत दोषी को 6 माह की कैद और जुर्माने की सजा दे सकती है। सजा के अलावा, 1953 के अधिनियम के तहत अपराध के कृत्य में उपयोग की जाने वाली उपज और वस्तुओं को 1953 के अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा 1953 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से जब्त और निपटान किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के अपराध को निर्धारित करने का प्राधिकारी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है जबकि जब्ती का आदेश देने वाला प्राधिकारी एक विधिवत अधिकृत वन अधिकारी है।

14. सबसे पहले जब्ती का आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, जिसकी अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होती है और फिर, अपीलीय प्राधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। संहिता के अंतर्गत किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश अंतिम है।

15. इस याचिका के गुणागुण पर विचार करने से पहले, इस याचिका की पोषणीयता के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक की आपत्ति से निपटना उचित है।

16. यह तर्क देने के लिए 1953 के अधिनियम की धारा 52ख के उप-खंड (5) पर भरोसा किया गया था कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को किसी भी न्यायालय के समक्ष और माननीय सर्वोच्च के निर्णय पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** (सुप्रा.) के मामले में प्रतिपादन किया।

17. यदि **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** (सुप्रा.) के मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने वाहन की अंतरिम रिहाई के लिए संहिता की धारा 451 के तहत एक आवेदन दिया था, जिसे जब्त कर लिया गया था। 1983 के एमपी अधिनियम 25 (इसके बाद '1983 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत अपराधों में शामिल होना। उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, जबकि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष

इस आधार पर अपील की गई थी कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

18. उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय उस वाहन की अंतरिम रिहाई के लिए आदेश पारित नहीं कर सकता था जिसके संबंध में 1983 के अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई थी, क्योंकि जिस वाहन के संबंध में जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई है, उसकी अंतरिम रिहाई के लिए न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भी माना गया कि ज़ब्ती की कार्यवाही अभियुक्तों को दोषी ठहराने की कार्यवाही से अलग है; जबकि पहले वाले पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए अपराध के कृत्य को संक्षेप में निर्धारित करने के लिए हैं, दूसरे आपराधिक अभियोजन के लिए हैं। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय 1983 के अधिनियम के तहत निहित वैधानिक रोक के बावजूद वाहन की अंतरिम रिहाई के लिए आदेश पारित नहीं कर सकता था।

19. वर्तमान मामले के तथ्य **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** (सुप्रा.) से स्पष्ट रूप से अलग हैं क्योंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित जब्ती के आदेश के खिलाफ अपील की थी, न कि किसी के खिलाफ। संहिता की धारा 451 के तहत आवेदन को अपास्त करने का आदेश। अंतरिम रिहाई के लिए आवेदन और ज़ब्ती के खिलाफ अपील में स्पष्ट अंतर है।

20. 1983 के अधिनियम की धारा 52 सी और 53 के अवलोकन से पता चलता है कि वाहन की अंतरिम रिहाई जिसके संबंध में जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई है, केवल धारा 53 के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकता है। इसलिए, अंतरिम रिहाई के लिए एक आवेदन उपरोक्त प्रावधानों के अलावा किसी भी प्राधिकारी द्वारा वाहन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम उदय सिंह** (सुप्रा.) के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया:

> *"61 मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 में अधिनियमित संशोधनों में निहित योजना यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट*

करती है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत एक याचिका में जो निर्देश जारी किया गया था। सीआरपीसी द्वारा मजिस्ट्रेट को वाहन की अंतरिम रिहाई का निर्देश देना, जिसे जब्त कर लिया गया था, कानून के विपरीत था। एक बार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के बाद सीआरपीसी की धारा 451 के तहत क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के लिए उपलब्ध नहीं था"।

21. उदय सिंह (सुप्रा.) के मामले में उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संहिता की धारा 451 के तहत न्यायालय को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग किया। जबकि, इस मामले में यह न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश की सत्यता की जांच कर रहा है, जैसाकि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

22. याचिकाकर्ता ने ज़ब्ती के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि ज़ब्ती का आदेश याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि के आदेश के बिना पारित किया गया है। इस न्यायालय को इस तर्क में कोई तथ्य नहीं मिला क्योंकि 1953 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई जब्ती की कार्यवाही मुकदमे या दोषसिद्धि की कार्यवाही के समानांतर चलती है। धारा 52(3) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी दोषसिद्धि के किसी भी आदेश के अभाव में संक्षेप में जब्ती का आदेश पारित कर सकता है। 1953 के अधिनियम की धारा 55 पर निर्भरता का कोई फायदा नहीं है। यह सच है कि धारा 55 जब्ती के आदेश को दोषसिद्धि के आदेश पर निर्भर करती है, हालाँकि, धारा 55 स्वयं धारा 52 के प्रावधानों के अधीन है। इसलिए, मुकदमे के समापन या दोषसिद्धि की प्रतीक्षा किए बिना जब्ती का आदेश पारित किया जा सकता है।

23. जैसा भी हो

24. यह उल्लेखनीय है कि 1953 के अधिनियम की धारा 52(3) जो प्राधिकृत अधिकारी को जब्ती का आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है, ऐसी शक्ति का प्रयोग 1953 के अधिनियम की धारा 52(5) के अधीन करती है जो यह प्रदान करती है जहां वाहन का उपयोग वाहन के मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया हो, वहां जब्ती का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

25. दिनांक 29.11.2021 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि 1953 के अधिनियम के तहत अपराध का कृत्य आकस्मिक था और यह मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना था।

26. तब एक प्रश्न उठ सकता है, क्या 1953 के अधिनियम की धारा 52ख(5) संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की इस न्यायालय की शक्ति पर बाधा उत्पन्न करती है?

27. संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का भंडार है। प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का सहारा ले सकता है।

28. उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित जब्ती के आदेश दिनांक 29.11.2021 के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपराध वाहन के चालक/मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना किया गया था। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद प्राधिकृत अधिकारी 1953 के अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा 5 में निहित स्पष्ट प्रावधानों के तहत वाहन को जब्त नहीं कर सकता था।

29. इस प्रकार जब्ती का आदेश मौलिक रूप से शून्य और स्पष्ट रूप से अवैध है। यह तथ्य कि वन अपराध बढ़ रहे हैं, किसी ट्रक को जब्त करने का कारण नहीं हो सकता, जब मालिक/चालक वन अधिनियम के तहत इसके अपराध में शामिल नहीं है। वाहन की ज़ब्ती का उपयोग बिजूका या निवारक के रूप में नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से मालिक के अपराध के बिना।

30. इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां यह न्यायालय तथ्यों और कानून की स्पष्ट त्रुटि को ठीक करने और पूरी तरह से अवैध जब्ती को अपास्त करने के लिए संहिता की धारा 482 द्वारा प्रदत्त अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसलिए, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए, संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय जब्ती के आदेश दिनांक 29.11.2021 और अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी के क्रमशः दिनांक 08.03.2022 और 29.04.2022 के आदेश को अपास्त करता है।

31. वर्तमान याचिका और स्थगन याचिका का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

125-Ramesh-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।